

STERLING TOOLS LIMITED

CIN : L29222DL1979PLC009668



WORKS : 5-A DLF Industrial Estate
Faridabad - 121 003 Haryana India
Tel : 91-129-227 0621 to 25/225 5551 to 53
Fax : 91-129-227 7359
E-mail : sterling@stlfasteners.com
website : stlfasteners.com

By NEAPS

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza",
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai-400051

Trading Symbol: STERTOOLS**By Listing Centre**

The Manager- Listing
BSE Limited
25th Floor, P. J. Towers
Dalal Street,
Mumbai - 400001

Scrip Code: 530759**Date: 4th February 2026****Subject: Newspaper publication of Unaudited Financial Results for the Third Quarter and Nine Months ended 31st December, 2025**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed herewith copies of the newspaper publication of Unaudited Financial Results in **Financial Express (English)- All Edition and Jansatta (Hindi)- Delhi Edition** on 4th February, 2026 for the quarter and nine months ended 31st December, 2025.

The afore-mentioned results were approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 3rd February 2026.

This is for your kind information and records.

For **STERLING TOOLS LIMITED****Komal Malik****Company Secretary & Compliance Officer****Encl.: As Above.**

केंद्रीय बजट से दिल्ली की सड़कों और यातायात को मिलेगी नई दिशा : वर्मा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ‘नेक्स्ट जेनरेशन बजट’ बताते हुए कहा कि यह भारत की आर्थिक नींव को मजबूत करने के साथ-साथ दिल्ली के विकास को नई गति देगा। मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस बजट से राजधानी के बुनियादी ढांचे, विशेषकर सड़क नेटवर्क, को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में लोक निर्माण विभाग को सड़क विकास के लिए केंद्र सरकार से 805 करोड़ रुपए मिले हैं और अगले वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कराने का प्रयास किया जाएगा। इस राशि से सड़कों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के कार्य बड़े पैमाने पर किए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वर्मा ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय के चलते विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 महीनों में शासन व्यवस्था में स्थिरता और पारदर्शिता आई है। उन्होंने केंद्रीय बजट को 2047 तक विकसित भारत और विकसित दिल्ली की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया।

राशन कार्ड सत्यापन को लेकर आप पर भ्रम फैलाने का आरोप भाजपा विधायक हरीश खुराना ने सरकार से श्वेत पत्र की मांग की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

राष्ट्रीय राजधानी में राशन कार्डों के पुनः सत्यापन को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। खुराना ने मांग की कि वर्ष 2015 से 2024 तक पूर्ववर्ती ‘आप’ सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए राशन कार्डों पर श्वेत पत्र लाया जाए। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखने की बात कही। प्रेस वार्ता में खुराना ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

दिल्ली की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुरूप गरीब परिवारों को होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में इसके लिए 242 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। योजना के तहत राजधानी के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष दो सिलेंडर के बराबर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस साल होली से पहले यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को 853 रुपए प्रति सिलेंडर दिए जाएंगे। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सार्वभौमिक है और एलपीजी या पीएनजी उपयोग करने वाले सभी राशन कार्डधारकों पर समान रूप से लागू होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को

मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला

होली और दिवाली पर हर राशन कार्डधारी को मुफ्त गैस सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपए



केंद्र सरकार की 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सबसिडी समायोजित करने के बाद 553 रुपए प्रति सिलेंडर की सहायता मिलेगी। वहीं, गैर-उज्ज्वला राशन कार्डधारक परिवारों को पूरी राशि 853 रुपए दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि त्योहारों के समय गरीब परिवारों की गरिमा और राहत सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। उन्होंने यह भी बताया कि योजना का अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 242.77 करोड़ रुपए होगा, जिसे एलपीजी कीमत, केंद्र की रियायत और लाभार्थियों की संख्या के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

सीआइसी का नोटिस मिलते ही ‘गुम’ फाइल हुई प्रकट आरटीआइ आवेदन के बाद नगर निगम के जवाब से आयोग हैरान

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा एक आरटीआइ आवेदन के जवाब में जिस फाइल को ‘नहीं मिलने’ की बात कही गई थी, वही फाइल केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) में मामला पहुंचते ही रहस्यमय तरीके से उपलब्ध हो गई। इस पर आयोग ने आश्चर्य जताया है।

यह मामला माडल टाउन क्षेत्र में एक अस्पताल के लेआउट को मंजूरी देने से जुड़े दस्तावेजों से संबंधित है। आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में एमसीडी के नगर नियोजन विभाग ने पहले कहा था कि संबंधित फाइल उपलब्ध नहीं है और उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। पहली अपील के दौरान भी विभाग ने यही रुख अपनाया। हालांकि, मामला जब केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष आया, तो अचानक

स्थानीय निकायों को 687 करोड़ की वित्तीय मदद

दिल्ली सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकायों को 687.22 करोड़ रुपए की तीसरी एवं अंतिम बौटीए किस्त जारी करने को मंजूरी दी है। इसमें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 673.12 करोड़, दिल्ली छावनी बोर्ड को 57.3 करोड़ और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को 8.36 करोड़ रुपए मिलेंगे। शहरी विकास मंत्री आशीष सुद ने कहा कि राशि केवल जनहित और विकासात्मक कार्यों में खर्च होगी, जिसमें स्वच्छता, आधारभूत ढांचा और नागरिक सुविधाओं के सुधार शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में एमसीडी को 500 करोड़ रुपए की एकमुश्त सहायता भी दी गई।

पुरानी दिल्ली के कायाकल्प की कमान अब मुख्यमंत्री के हाथ

पुरानी दिल्ली के कायाकल्प की कमान अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हाथों में रहेगी। रेखा गुप्ता को शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में लोकनिवास उपराज्यपाल सचिवालय) से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास और विरासत संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। एसआरडीसी के माध्यम से पुरानी दिल्ली को आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास और विरासत संरक्षण को लेकर एक व्यापक योजना तैयार की है।

मामला माडल टाउन क्षेत्र में एक अस्पताल के लेआउट को मंजूरी देने से जुड़े दस्तावेजों से संबंधित है।

फाइल से जुड़ी जानकारीयां सामने रख दी गई। इस पर सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने हैरानी जताते हुए सवाल उठाया कि सीआइसी से सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद वह फाइल कैसे मिल गई, जिसे पहले दो बार पेश करने में असमर्थता जताई गई थी। आयोग ने कहा कि इस तरह के पूरी तरह विपरीत रुख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सीआइसी ने टिप्पणी की कि केवल यह कहना कि फाइल नहीं मिल रही है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना

अधिकारी (पीआइओ) की वैधानिक जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त नहीं करता। आयोग ने यह भी चिंता जताई कि आधिकारिक जवाबों में पीआइओ का नाम और संपर्क विवरण जैसी बुनियादी जानकारीयां तक शामिल नहीं थीं, जो आरटीआइ कानून की भावना के खिलाफ है। आयोग ने यह भी कहा कि आवेदक को जानकारी देने की औपचारिक प्रक्रिया अपनाने के बजाय केवल आंतरिक खोज मेमो जारी करना यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। सीआइसी ने इसे सूचना के खुलासे से बचने का प्रयास बताया। समयवार को जारी आदेश में आयोग ने एमसीडी को चार सप्ताह के भीतर बिंदुवार और पूर्ण उत्तर देने का निर्देश दिया है। साथ ही पीआइओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।

‘कोचिंग सेंटर में हुई मौतों के मामले में अब जांच की जरूरत नहीं’

नई दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को स्थानीय अदालत में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि 27 जुलाई, 2024 की शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के भूतल में बारिश का पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले में अब जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय एंजंसी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी सबूत एकत्र कर विभिन्न दृष्टिकोणों से उनकी जांच की गई है। एंजंसी ने मृत अभ्यर्थी के पिता द्वारा मामले की जांच को आगे बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया। मृतक नविन दल्विन के पिता दलविन सुरेश के वकील अभिजीत आनंद ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि केंद्रीय एंजंसी के जांच अधिकारी (आईओ) ने ‘निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच’ नहीं की।

विश्व कैंसर दिवस आज, विशेषज्ञों ने बताया कैंसर के मामले 2045 तक 24.5 लाख सालाना होने का अनुमान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

विश्व कैंसर दिवस पर इंडियन कैंसर सोसाइटी (दिल्ली शाखा) के विशेषज्ञों ने आगाह किया कि भारत में हर साल नए कैंसर मामलों की संख्या 2045 तक 24.5 लाख तक बढ़ सकती है, जबकि वर्तमान में यह लगभग 15 लाख है। सोसाइटी की दिल्ली अध्यक्ष ज्योत्सना गोविल ने कहा कि समय पर जांच होने से इलाज की लागत कम होती है और नतीजे बेहतर आते हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 में कैंसर उपचार की पहुंच बढ़ाने के लिए चुनिंदा दवाओं पर कर में छूट

घने कोहरे का कहर, यातायात पर पड़ा असर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 फरवरी।

दिल्ली में मंगलवार सुबह घने कोहरे ने राजधानी के कई हिस्सों को अपनी चादर में लपेट लिया, जिससे दृश्यता में भारी कमी आई। खासतौर पर सफ़दरजंग में दृश्यता 50 मीटर तक और पालम में 100 मीटर दर्ज की गई। घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 220 उड़ानों में देरी हुई, जबकि 40 उड़ानों को रद्द कर दिया गया और 10 उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार, दिल्ली में आने वाले दिनों में कोहरे का असर और गहरा सकता है। आइएमडी ने आज यानी चार फरवरी के लिए ‘पीली चेतावनी’ जारी की है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 10-16 किलोमीटर प्रतिघंटा रहने का अनुमान है।